International Journal of Applied Research 2017; 3(3): 483-484

**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 5.2
IJAR 2017; 3(3): 360-362
www.allresearchjournal.com
Received: 05-01-2017
Accepted: 07-02-2017

**आशा रानी**
असिस्टैंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, वैश्य पी. जी. कॉलेज, भिवानी, हरियाणा, भारत

**Correspondence**
**आशा रानी**
असिस्टैंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, वैश्य पी. जी. कॉलेज, भिवानी, हरियाणा, भारत

# भारत में बेरोजगारों की व्यथा

## आशा रानी

### प्रस्तावना

आज समस्त भारत में भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आडम्बर, अनुशासनहीनता एवं बेरोजगारी का बाजार गर्म है। चारों ओर हताशा–निराशा छाई हुई है। इन सबका कारण क्या है? मेरे विचार से आधुनिक शिक्षा ही इस समस्या का कारण है क्योंकि प्रारम्भ से बच्चों में सृजनात्मक, तकनीक एवं रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसी देश या समाज का नौजवान तबका ही कर्णधार होता है। लेकिन हमारे राजनेताओं ने स्वार्थ लिप्सा के कारण तथा पूंजीपतियों ने, मुनाफे को सब कुछ समझने वालों ने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाहों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे छुटकारा पाना असम्भव दिखाई पड़ता है।

इतिहास के हर दौर में देश और समाज को सही दिशा देने वाला नौजवान ही आज खुद दिशाहीन है तथा अंधी गलियों में भटक रहा है।

''अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 रुपये से कम पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 83.6 करोड़ है। 77 प्रतिशत लोगों को जरूरत से कम अनाज मिल पाता है। तीन चौथाई आबादी को भोजन में जरूरी पोषक तत्त्व और प्रोटीन नहीं मिल पाते। इन सब नागरिकों के पास कोई नौकरी, अपना रोजगार होता, तो ये भला भूखे पेट या आधे पेट क्यों रहते, ग़रीबी और कुपोषण के शिकार क्यों होते?''[1]

वास्तव में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सरकारी आंकड़ों व दावों से अधिक भयावह है। देश में नये रोजगार तो दूर की बात है लेकिन जो रोजगार पर लगे हुए हैं, उन्हें तालाबंदी व छंटनी करके निकाला जा रहा है। 1990 के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के कारण अत्यधिक भयावह स्थिति बन गई है। अतः आगे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जायेंगे। जो सार्वजनिक कम्पनियाँ जनता के खून पसीने को निचोड़कर तैयार की गई है, अब सरकारें उन्हें पूंजीपतियों को बेच रही हैं। चाहे वे कम्पनियाँ कितना ही मुनाफा कमा रही हैं लेकिन फिर भी सरकार उसको बेचने के लिए आमादा है।

''2016 में लेबर ब्यूरो ने 8 क्षेत्रों की 2000 इकाइयों का नमूना सर्वे किया। इससे पता चलता है कि इस साल पहली तिमाही में सीधे या ठेके के जरिये रोजगार में कमी आई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 18 प्रतिशत और आभूषण क्षेत्र में 16 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। पूरे वित्त वर्ष 2015–2016 में रोजगार के हालात बद से बदतर होते गये हैं।''[2]

बहुत से नौजवान केन्द्रीय और प्रादेशिक लोक सेवा आयोग की परीक्षा के तैयारी में सतत् प्रयत्न एवं तपस्या करते हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है तो 3 लाख में से केवल 300 का चयन किया जाता है। यह कैसी विडम्बना है। समझ से परे है। मेक इन इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया और डिजिटल इण्डिया आदि कार्यक्रमों में देश विकास व रोजगार सर्जन के दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं।

''कुछ समय पहले यू.पी. सचिवालय में 368 भर्ती निकली थी, जिसकी न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। आवेदन करने वालों की संख्या 23 लाख 25 हजार पहुँच गई। इसके लिए 255 पीएच.डी. धारी, 10 हजार एम.बी.ए. और लाखों बी.टेक छात्रों ने आवेदन किया था।''[3]

भारत में जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए प्रत्येक को नौकरी नहीं दी जा सकती है। एक झूठ सौ बार बोलने से वह सच हो जाती है। अतः शासक वर्ग इस सिद्धान्त को आधार बनाकर जोरदार ढंग से प्रचार में जुट जाता है कि सारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। आज सारे संसार में मुनाफे को आधार मानकर पूँजीपति पूँजी का निवेश करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अनेक प्रकार के हथकण्डे अपना कर यह प्रचार करती है कि बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। सबसे पहले माल्थस ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया था, जिससे पूंजीपतियों का सहारा मिल गया।

''अब विचार करने योग्य बात है कि क्या जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है?''[4]

**तालिका 1**

| | जनसंख्या वृद्धि | रोजगार वृद्धि |
|---|---|---|
| 1972 | 2.27 | 2.73 |
| 1977–78 | 2.19 | 2.17 |
| 1983–1987–88 | 2.14 | 1.54 |
| 1987–1993–94 | 2.10 | 2.43 |
| 1993–94, 1999–2000 | 1.93 | 0.98 |

उपर्युक्त आंकड़ों से साफ है कि 1972–73 और 1977–78 के बीच पांच साल रोजगार में वृद्धि की दर 2.73 प्रतिशत सालाना थी जो जनसंख्या वृद्धि पर 2.27 प्रतिशत से अधिक थी। 1993–94 – 1999–2000 के बीच उलटी स्थिति हो गई। पांच साल में रोजगार वृद्धि दर घटकर 0.98 रह गई। जो इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.93 प्रतिशत से कम रह गई।''[5]

अतः इससे यह भलीभांति सिद्ध होता है कि सरकार की ग़लत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं। सरकार की निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सरकार निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को त्याग कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशे। इस समस्या का गम्भीरता के साथ निपटारा करने की आवश्यकता है। सरकार तरह–तरह के भ्रम फैलाती है कि पैसा नहीं है। विधायकों और सांसदों के वेतन एवं भत्ते एक दिन में कई सौ गुणा बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? किसानों–ग़रीबों के लिए पैसा नहीं है। लेकिन नेताओं के जन्मदिन पर करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है। पूंजीपतियों को सब्सिडी देने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? सरकार धनकुबेरों को लगातार छूट देती जा रही है।

''कारपोरेट महाप्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए आयकर विभाग ने 29 जनवरी 2015 को अपने सभी क्षेत्र अधिकारियों को आदेश दिया कि शेयरों की लेनदेन से होने वाली आय पर कर वसूलने के लिए किसी भी कम्पनी के खिलाफ कोई कारवाई न करें क्योंकि इनसे देशी–विदेशी कारपोरेट समुदाय और पूंजी निवेशक 'आतंकित हो जायेंगे। सन् 2007 जब वोडाफोन ने हचिन्सन हच का मालिकाना हक खरीदा तब इसे लेन–देन के लिए सरकार को 11,200 करोड़ रुपया कर देना था। उसने नहीं दिया। इसके साथ ही उसे 8500 करोड़ रु. हस्तान्तर कर भी देना था, उसने वह भी नहीं दिया। उसकी कुल राशि बकाया कर, ब्याज और जुर्माना मिला कर 23000 करोड़ रुपया हो गया। उसने बकाया आज तक नहीं दिया।''[6]

यदि कोई सामान्य व्यक्ति देनदारी नहीं देता है तो उस पर सख्त कारवाई कर दी जाती है। सरकार गोली चलाने में देर नहीं करती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुलाम है। अन्य कितनी और कम्पनियाँ जिन पर भारी–भरकम राशि बकाया है। उनको तो 573000 करोड़ रु. की 2014–15 में छूट प्रदान कर दी। यही समझ से परे की बात है कि ये कम्पनियां देश को खोखला कर रही हैं। हमारे राजनेता तमाशबीन बने हुये हैं। 'इस्ट इण्डिया कम्पनी' की तरह ये सभी कम्पनियां पुनः देश को गुलाम तो नहीं बना देंगी।

बेरोजगारी की समस्या की जड़ में पहुँच पर इसे समाप्त करना होगा। यह किसी मजदूर, किसान, नौजवान या सरकारी कर्मचारी के बस की बात नहीं है। इसके मुख्य कारण की जानकारी प्राप्त करनी होगी। बेकारी, बेरोजगारी का असली कारण है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था ने हमारे लघु उद्योग, हस्त करघा शिल्पी और बढ़ई आदि को बर्बाद कर दिया। मशीनीकरण तथा कम्प्यूटर ने बेरोजगारी बढ़ाने में योगदान दिया। अब बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर गई।

''नवीं मुम्बई की थायरोकेयर कम्पनी में 200 तकनीशियन काम करते हैं। वे शाम 8 बजे से 12 घण्टे लगातार काम करके 45 हजार सैम्पलों पर 2 लाख टेस्ट करते हैं। भारत 1300 केन्द्रों से मंगाये गये सैम्पलों से थायरायड, किडनी और लीवर की बीमारियों का पता लगाया जाता है। लगभग एक दशक पहले 1000 तकनीशियन यही काम कई दिनों के प्रयास से पूरा करते थे, जो उससे अब 5 गुना कम तकनीशियन एक रात में पूरा करते हैं। उनके ऊपर काम का भारी दबाव रहता है। कम्पनियाँ मुनाफे की वृद्धि के लिए छंटनी से भी नहीं कतराती हैं, चाहे इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायें।''[7]

बेरोजगारी से तंग आकर नौजवान अपराध की दुनिया में कदम रखने लगते हैं। इससे उनके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। जो सपने संजोये थे। उनको ग्रहण लग जाता है। यह उन युवकों का दोष नहीं है, अपितु सरकार ने उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि युवा–शक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये। अगर सरकार बेरोजगारी की समस्या का सही समाधान कर दे तो समाज की सभी समस्यायें स्वतः ही समाप्त हो जायें। अतः इस ओर ध्यान वांछित है।

''नौजवानों के दिलों–दिमाग की ताकत को बिजली में रूपान्तरित करते हुए, देश–निर्माण और मानव निर्माण में लगाने के लिए जिस बिजली घर की जरूरत होती है, वह हिन्दुस्तान से नदारद है। अब देश की उन्नति हो तो कहाँ से हो और कैसे हो। जिस देश में नौजवान मारे–मारे फिरते हैं, बेकार रहते हैं, भूखों मरते हैं, (बौद्धिक और हार्दिक विकास के लक्ष्य ही जहाँ गुम हैं) तो उस देश का नौजवान अगर अपनी खाली जेब और भूख की यन्त्रणा को अपने दुर्भाग्य की, चवन्नी छाप एक्ट्रेसों की सूरत देख कर दो मिनट के लिए भूलना चाहता हो, तो उस नौजवान की तृषित आँखों को लोग भले ही गलत समझें, हम उनके बारे में कोई गलतफहमी में नहीं हैं, क्योंकि हमारा नौजवान बेहद सच्चा है और बेहद अच्छा है, उसमें बड़ी आग है और बेहद मिठास है। वह दुनिया को उलट सकता है और उलट कर फिर पलट सकता है, लेकिन उसके दिलो–दिमाग की ताकत को मानवी बिजली में रूपान्तरित करने वाला बिजलीघर कहाँ है?''[8]

निजीकरण के नाम पर बड़ी–बड़ी कम्पनियों को बेचा जा रहा है। जैसे भेल, गेल, ओ.एन.जी.सी., भारत पेट्रोलियम, सेल आदि विनिवेश के नाम पर बिकने की तैयारी में हैं। इनमें कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। 2014 में नई सरकार आने के बाद रेलवे के माल भाड़े में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। 9 महीने में 2178 करोड रु. मुनाफा हुआ। नौकरी तलाशने वाले नवयुवकों की आशा की किरण जागी। लेकिन वाई–फाई, हाई स्पीड ट्रेन और मनोरंजन की सुविधाओं ने नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। वैश्वीकरण ने लाखों किसानों को उजाड़ दिया, उद्योग आदि में नौकरी आदि लगने की कोई सम्भावना दृष्टिगोचर होती नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से लोगों का रहन–सहन अन्य सभी सुविधायें छिन्न–भिन्न हो गई। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। निराशा है। हताशा है।

''बेरोजगारी का दंश झेल रहे एक नौजवान को एलईडी बल्ब की एक मार्केटिंग कम्पनी ने साक्षात्कार के बाद नौकरी पर रख लिया। उसके काम का इलाका रामपुर, हिमाचल प्रदेश था। वेतन कम था लेकिन उसने सोचा कि बेरोजगार रहने से कुछ काम करना बेहतर है। उसे नौकरी का अनुभव और हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में घूमने का मौका मिलेगा। काम के दौरान एक आश्चर्यचकित कर देने वाली एक घटना का सामना करना पड़ा। वेबसाइट खोलकर जब उसने रामपुर इलाके में अपने कामों का ब्योरा दर्ज करना चाहा तो वह इलाका कम्पनी की वेबसाइट पर था कि नहीं। उसे सन्देह हुआ। जाँच–पड़ताल करने पर उसे पता चला कि कम्पनी में भारी गड़बड़ी चल रही है। कोई बड़ा घोटाला जड़ें फैला रहा है। उसने ऊपर के अधिकारियों से उसकी शिकायत की। उन्होंने उलटा उस पर क्षमता की कमी और लापरवाही का आरोप लगा कर उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।''[9]

आइये, समय तुम्हें पुकार रहा है। सभी उठो, जागो, संगठित हो जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सम्भल जाओ। मौका हाथ से निकलता जा रहा है। यदि अभी नहीं होश सम्भाला तो बहुत देर हो जायेगी। राजनेताओं ने देश को उजाड़ दिया है। बेरोजगारी ही नहीं अपितु बहुत गम्भीर समस्याएं सभी पार्टियों ने पैदा कर दी हैं। सभी संगठित हो करके भारत के नवनिर्माण का संकल्प लेकर के दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ें। यद्यपि डगर मुश्किल है लेकिन असम्भव नहीं है। अलग–अलग, निराश और परेशान हो करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस सोने की चिड़िया को इन राजनेताओं से बचाने के लिए समुज्ज्वल भारत के भविष्य के लिए पूर्ण रूप से संगठित हो करके इस व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन करना होगा। अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के जात–पात, छुआछूत को त्याग कर, पूंजीपतियों से, सट्टेबाजों से नेताओं से, नौकरशाहों से बचाने के लिए प्रयत्नशील होना होगा। देश को पुनः गौरवान्वित करने के लिए, लूट तन्त्र, लठ तन्त्र बन्द करके देश की रक्षा के लिए आगे आयें। विदेशी कम्पनियों को लूट की गारन्टी दे करके बुला रहे हैं। अब नौजवानों को अपना रास्ता तय करना है। कब तक हम इस दुर्व्यवस्था को सहन करते जायेंगे। बेकारी–बेरोजगारी–भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, सितम सभी समस्याओं का निदान करने के लिए जुट जाओ। तभी हम इस आन्दोलन में सफल हो सकते हैं तथा देश के समुज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. भारत नौजवान सभा बढ़ती बेरोजगारी, पृ.4।
2. बेरोजगारों की कथा व्यथा, पृ.5।
3. बढ़ती बेरोजगारी, प्रधानमंत्री कौशल विकास की हकीकत, पृ. 9।
4. रोजगार अवसर टास्क फोर्स की रिपोर्ट योजना आयोग, पृ.19, जून 2001।
5. बढ़ती बेरोजगारी, 23–24।
6. वही, 31।
7. वही, 35।
8. वही, 20।
9. वही, 47।